बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 18 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 24 अक्तूबर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

विधानसभा सत्र आज से, पूर्ण राज्य के साथ ही जमीन और बिजली पर होगी बड़ी बहस

जम्मू । विधानसभा का मानसून सत्र वीरवार से शुरू होगा। करीब छह माह बाद होने जा रहा यह सत्र सीमित जरूर रहेगा लेकिन इसमें बड़ी बहस सुनाई देगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही सत्र को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सदन में एक विधायक अधिकतम दस सवाल पूछ सकेगा। 450 सवाल सदन में उठने वाले हैं। 13 प्राइवेट मैंबर्स बिल और 55 प्रस्ताव भी विधानसभा को भेजे गए हैं। बीते छह माह में हुए तमाम बड़े घटनाक्रमों पर राजनीतिक दलों ने सदन में प्रस्ताव भेजकर चर्चा मांगी है। मंत्रिमंडल ने बीते दिनों पंचायती राज एक्ट 1989, शॉप एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बिल और गुड्स एंड सर्विसेज 2017 में बदलाव को मंजूरी दी है.

लाडो लक्ष्मी योजना: महिलाएं तय करेंगी मासिक कितना चाहिए पैसा, लाभ पाने के लिए 25 अक्तूबर तक करना होगा

सिरसा । दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 2100 रुपये की किस्त सरकार हरियाणा दिवस एक नवंबर को जारी करने जा रही है। इस योजना के लिए जिले से 21,000 महिलाएं पात्र मिली हैं, जिन्होंने आवेदन किया है। जो महिलाएं एक नवंबर को पहली किस्त पाना चाहती है, उन्हें 25 अक्तूबर तक आवेदन करना होगा। अहम बात यह है कि यह 25,200 रुपये की किस्त आवेदनकर्ता की सालाना आय में शामिल हो जाएगी। अब आवेदनकर्ता को चयन करना होगा कि वह 2100 रुपये या उससे कम कितना पैसा बतौर किस्त प्रतिमाह प्राप्त करना चाहता है। जिससे कि वह सरकारी की अन्य सुविधाओं से वंचित न रहे। 25 अक्तूबर तक आवेदन करने वाली महिलाएं एक नवंबर को जारी होने वाली किस्त के लिए पात्र होंगी। गौरतलब है कि एक लाख रुपये तक आय वाले व्यक्ति का हैप्पी कार्ड बनाया जाता है और एक लाख 80 हजार तक आय वाले परिवार का बीपीएल कार्ड होता है। महिलाएं अपनी मर्जी अनुसार प्रतिमाह किस्त का पैसा ले सकती हैं। जिससे कि उनकी फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा प्रभावित न हो। इस योजना के तहत 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए मोबाइल एप से आवेदन होता है। सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर ही एप बनाई है। एप को डाउनलोड कर ही आवेदन किया जा सकता है और एक मोबाइल नंबर से पांच महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद दूसरे मोबाइल नंबर का प्रयोग करना होगा। आवेदन करने के

बाद दस्तावेज का सत्यापन होगा और मोबाइल पर पात्र होने संबंधी मैसेज आएगा। एप से महिला को तय करना है कि उसे बतौर किस्त प्रति माह कितना पैसा प्राप्त करना है। अधिकारियों के अनुसार अभी तक 21,000 महिलाओं के दस्तावेज ही सत्यापित हुए हैं और जो पात्र हैं। आकलन के अनुसार सिरसा में अभी बड़े स्तर पर महिलाओं ने अपना पंजीकरण इस योजना के तहत करवाया नहीं है। अनुमान है कि एक लाख 15 हजार के आसपास महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हो सकती हैं। उम्मीद है कि प्रथम किस्त जारी होने के बाद बड़े स्तर पर महिलाएं इस योजना के तहत आवेदन करेंगी।

वहीं, इस योजना का दूसरी योजनाओं पर प्रभाव को देखते हुए भी परिवार के लोग संशय में है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सत्यापन का काम तेजी से हो रहा है। 21 हजार महिलाओं के आवेदनों का सत्यापन हो चुका है। 25 अक्तूबर तक आवेदन करने वाली महिलाएं एक नवंबर को जारी होने वाली किस्त के लिए पात्र होंगी। इस योजना के तहत दिया गया पैसा, सालाना पारिवारिक आय में गिना जाएगा। सरकार ने महिलाओं को विशेष सुविधा दी है कि वह अपने स्तर पर तय कर सकती हैं कि उन्हें मासिक किस्त कितनी चाहिए।

हिमाचल प्रदेश: वजूद खो रहे परंपरागत घराट, कुल्लू में तीन साल में 451 का मिटा अस्तित्व

शिमला । पहाड़ की पथरीली ढलानों में कभी घर्र-घर्र की गूंजती आवाज... जीवन की लय हुआ करती थी। इन घराटों की दहलीज पर लोकगीत पनपते थे और प्रेम के किस्से जन्म लेते थे। लेकिन समय के साथ ये घराट मिटते गए और इनके साथ एक भावनात्मक अध्याय भी थम गया। कुल्लू जिले में बीते तीन साल में ही 451 घराट अपना वजूद खो गए। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। हालांकि, करीब ढाई दशक पहले जिला में 2,500 से अधिक परंपरागत घराट हुआ करते थे। जैसे ही जिले में बागवानी और नकदी फसलों की ओर लोगों का रुझान बढ़ता गया, तब से घराट का वजूद खतरे में पड़ना शुरू हो गया था। इससे परंपरागत कृषि करने वाले किसानों की संख्या में भी काफी गिरावट आई और घराट में पिसाई के लिए अनाज न मिलने से ये घराट वीरान पड़ने लगे, रही सही कसर आपदा ने पूरी कर दी। लिहाजा, अब जिला में करीब 500 घराट ही बचे हैं, जिनमें चालू हालत में महज 200 के करीब ही बच पाए हैं। ये घराट उन क्षेत्र के नालों में हैं, जहां अभी भी गेहूं, मक्की, जौ, कादरा, सलियारा, काउणी, चीणी आदि परंपरागत अनाज की खेती हो रही है और इन नालों में काफी लंबे अरसे से कोई बाढ़ नहीं आई। बीते तीन वर्षों में बाढ़ के कारण तबाह हुए घराटों की बात करें तो वर्ष 2023 की बाढ़ ने सैंज की पिन पार्वती, पार्वती, ब्यास, सहित अन्य नालों में आई बाढ़ ने 415 घराट तबाह किए थे। जबकि वर्ष 2024 में भी जिलाभर के नदी-नालों में आई बाढ़ से 28 घराट नष्ट हुए थे। इस बार आई आपदा में 8 घराट का वजूद खत्म हो गया। जानकारों का मानना है कि जब से विद्युत प्रोजेक्ट लगने शुरू हुए, उससे कई नाले सूख गए और घराट बंद होने शुरू हुए। जबकि बिजली से चलने वाली चक्की के कारण भी इस पर काफी असर देखने को मिला। साहित्यकार डॉ. सूरत ठाकुर का कहना है कि घराट के कम होने का सबसे बड़ा कारण विद्युतीकरण रहा है।

एलएबी और केडीए के प्रतिनिधियों की गृह मंत्रालय के अधिकारियों संग हुई बैठक, तल्खी गायब...सकारात्मक रहा रुख

जम्मू । चार महीने के इंतजार के बाद आखिरकार बुधवार को लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के प्रतिनिधियों की केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लद्दाख के मुद्दों पर बुधवार को दिल्ली में अहम बैठक हुई। बैठक में शामिल लद्दाख के प्रतिनिधियों ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता में कहीं कोई तल्खी नजर नहीं आई। गृह मंत्रालय ने मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। कर्तव्य भवन-3 में आयोजित यह बैठक लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लद्दाख के नेतृत्व और गृह मंत्रालय (एमएचए) के बीच पहली औपचारिक वार्ता है। हाई पावर कमेटी की इस बैठक में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों ने लद्दाख को पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ ही संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की पुरानी मांग उठाई। उन्होंने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत

लगाए गए आरोपों को खारिज किए जाने के साथ ही लेह हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने की भी मांग रखी। बैठक में शामिल नेताओं ने बताया कि पिछली बैठकों के विपरीत गृह मंत्रालय के अधिकारियों का रुख सकारात्मक दिखा। उन्होंने उनकी मांगों पर उच्चस्तर पर कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया। जल्द ही एक और बैठक बुलाए जाने पर सहमति बनी। बैठक में शामिल लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने कहा कि केंद्र सरकार के नुमाइंदों के लहजे में लद्दाख के मुद्दों को लेकर गंभीरता झलकी है। हमने अपनी सभी मांगों को गृह मंत्रालय के सामने रखा है। उम्मीद है कि अगली बैठक में मांगों पर कुछ न कुछ निर्णय अवश्य होगा। सांसद ने कहा कि गृहमंत्रालय के अफसरों ने सभी मुद्दों पर बगैर किसी टालमटोल के सुनवाई का भरोसा दिया है। कहा कि एक ही बैठक में समाधान नहीं निकलेगा। बातचीत में समय लगता है। अगली बैठक की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेह एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष थुपस्तान छेवांग ने की। इसमें बौद्ध बहुल लेह और शिया बहुल कारगिल, दोनों क्षेत्रों के वरिष्ठ राजनीतिक प्रतिनिधि शामिल थे। लद्दाख के प्रतिनिधियों ने अपनी जमीन, संस्कृति और रोजगार के लिए संवैधानिक गारंटी पर अपनी बातें रखीं। उनका कहना था कि वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होने पर लद्दाख में इन सुरक्षा उपायों का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अनिर्णायक दौरों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए बैठक के मिनट्स जारी करने के साथ समय सीमा तय करने और फैसले लागू करने पर जोर दिया। लद्दाख में आरक्षण को लागू किए जाने पर भी प्रतिनिधियों की गृह मंत्रालय के नुमाइंदों के साथ चर्चा हुई। कुछ माह पहले केंद्र सरकार की ओर से लद्दाख के बेरोजगारों को रोजगार के लिए डोमिसाइल नीति घोषित की गई थी,

सरकारी होटलों में एक नवंबर से 40 फीसदी तक मिलेगी छूट

शिमला । प्रदेश के 44 सरकारी होटलों में एक नवंबर से 20 दिसंबर तक कमरों की बुकिंग पर 20 से 40 फीसदी छूट मिलेगी। राज्य पर्यटन विकास निगम ने इस अवधि के लिए विंटर डिस्काउंट जारी कर दिया है। लवी और रेणुका मेले में रामपुर में 11 से 15 नवंबर और रेणुका में एक से पांच नवंबर तक डिस्काउंट का लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश के चार होटलों मनाली लॉग हट, एप्पल ब्लासम फागू, पैलेस होटल चायल और कसौली के न्यू रॉस कॉमन होटल में 40 फीसदी तक कमरे सस्ते मिलेंगे। इसके अलावा 30 होटलों में 20 फीसदी, दो में 25 और आठ में 30 फीसदी विंटर डिस्काउंट लागू होगा। 21 दिसंबर से सभी होटलों में सामान्य किराया फिर से लागू होगा। निगम के महाप्रबंधक की ओर से इस बाबत सभी होटल प्रबंधकों को पत्र जारी किया गया है। पर्यटन विकास निगम ने सर्दियों में पर्यटकों को लुभाने के लिए इस खास ऑफर की घोषणा की है। सर्दियों के दौरान प्रदेश में आने वाले सैलानियों की अच्छी आमद रहती है।

इस ऑफर से घरेलू पर्यटन को और बल मिलने की उम्मीद है। पर्यटन निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह योजना ऑफ सीजन में पर्यटकों को राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए प्रेरित करेगी। सर्दियों में मनाली, कुफरी, फागू, चायल, कसौली और नारकंडा बर्फबारी के आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं। ऐसे में रियायती दरों पर होटल बुकिंग से राज्य की पर्यटन आमदनी में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। हमीरपुर के होटल हमीर, सुंदरनगर के सुकेत, रोहड़ू के चांशल, नूरपुर के होटल नूपुर, चंबा के इरावती, दाड़लाघाट के बाघल, ज्वालामुखी के होटल ज्वालाजी, स्वारघाट के हिलटॉप, बुशहर रिजेंसी रामपुर, धर्मशाला के कुनाल, परवाणू के शिवालिक, पांवटा साहिब के यमुना, पौंग डैम के कैंपिंग साइट, खड़ापत्थर के गिरिगंगा, चामुंडा के यात्री निवास, कसौली के ओल्ड रॉस कॉमन, सराहन के श्रीखंड, जोगिंदरनगर के ऊहल, मैकलोडगंज के भागसू, कुल्लू के सरवरी, शिमला के पीटरहॉफ, मैक्लोडगंज के क्लब हाउस, राजगढ़ के टूरिस्ट इन, भरमौर के गौरीकुंड, केलांग के चंद्रभागा, मनाली के कुंजुम, नारकंडा के हाटू, डलहौजी के गीतांजलि, क्यारीघाट के मेघदूत और डलहौजी के मणिमहेश होटल में 20 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा।

शिमला के होटल हॉलीडे होम, रेणुका के रेणुका जी होटल में 25 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा। भरवाई के चिंतपूर्णी हाइटस, पालमपुर के न्यूगल, बिलासपुर के लेक व्यू, पालमपुर के टी बड, धर्मशाला के होटल धौलाधार, बड़ोग के पाइनवुड, चायल के पैलेस होटल एनएक्ससी और नालदेहरा के गोल्फ ग्लेड होटल में कमरों की बुकिंग पर 30 फीसदी तक छूट मिलेगी।

हाईकोर्ट का अहम आदेश: मृतक के बालिग बच्चे भी हो सकते हैं उसके

चंडीगढ़ । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि मृतक के बालिग बच्चे भी उस पर आश्रित हो सकते हैं। हाईकोर्ट मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि उन्हें मुआवजा दावा करने का पूर्ण अधिकार है और आगे यह ट्रिब्यूनल को तय करना है कि वे असल में आश्रित है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि इसमें आयु का कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। याचिका दाखिल करते हुए करनाल निवासी महिला ने बताया कि उसके पति की 12 मार्च 2017 को मोटर वाहन दुर्घटना में मौत हो गई थी। याची ने बताया कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल करनाल ने उसके पति की मौत के लिए केवल 15 लाख 67 हजार रुपये जुर्माना तय किया जो बेहद कम है। याची ने बताया कि राम गोपाल हादसे से पहले प्रतिमाह 40 हजार रुपये कमाता था जबकि ट्रिब्यूनल ने उसकी आय प्रतिमाह केवल 12 हजार ही मानी थी। ट्रिब्यूनल ने राम गोपाल की आय आधार कार्ड के अनुरूप 51 साल मानी जबकि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी आय 45 वर्ष थी। याचिका का विरोध करते हुए प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने राम गोपाल की आय बिल्कुल सही मानी है क्योंकि 40 हजार रुपये आय से जुड़ा कोई दस्तावेज ही मौजूद नहीं है। साथ ही प्रतिवादियों ने कहा कि मुआवजा याचिका मृतक के बालिग बेटों ने दाखिल की है जिन्हें उस पर आश्रित नहीं माना जा सकता है। प्रतिवादियों हाईकोर्ट से अपील की कि इस याचिका को खारिज किया जाए। कोर्ट ने कहा कि मृतक की आयु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 45 साल मानी जानी चाहिए और बिना दस्तावेजों के ट्रिब्यूनल ने मृतक की आय 12 हजार रुपये सही आंकी है। कोर्ट ने कहा कि याची के बेटे भले ही बालिग हों लेकिन वे उसके कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं। उन्हें मुआवजा याचिका दाखिल करने का अधिकार है और वे पात्र हैं या नहीं यह तय करने का अधिकार ट्रिब्यूनल को है।

सम्पादकीय...

संस्कृति के बहाने हिजाब की पैरवी

केरल में कोच्चि के एक मिशनरी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की जब हिजाब पहनकर आने लगी तो वहां के अधिकारियों ने कहा कि वह स्कूल यूनिफार्म में ही आए। इस पर विवाद हो गया और केरल के शिक्षा मंत्री वी. सिवनकुट्टी भी इसमें कूद पड़े। उन्होंने स्कूल को आदेश दिया कि लड़की को हिजाब पहनकर आने दिया जाए। उन्होंने एक जांच भी बिठा दी, जिसमें कहा गया कि स्कूल के आचरण से बच्ची को बहुत परेशानी हुई। कुट्टी ने यह भी कहा कि स्कूल का इस तरह का आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के मानकों के खिलाफ है। बाद में स्कूल अधिकारियों ने बच्ची के माता-पिता से बात की, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि राजनीतिक दल एसडीपीआइ विवाद भड़काने में लग गया। उसके सदस्यों ने स्कूल वालों के साथ बदतमीजी की, जिनमें से अधिकांश नन थीं। हिजाब का मामला केरल हाई कोर्ट भी पहुंचा, जिसने स्कूल को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए। इस सबके बीच बच्ची के माता-पिता ने कहा कि वह अपनी बेटी का दाखिला किसी अन्य स्कूल में कराएंगे। केरल सरकार ने इसमें बच्ची की मदद करने की पेशकश की यानी वह भी उस लड़की को हिजाब सहित पढ़ने की अनुमति देने के पक्ष में खड़ी हो गई। सवाल यह है कि क्या स्कूल अब मजहबी आदेशों से चलेंगे या अपने कायदे-कानूनों और परंपरा से? सिवनकुट्टी जिस वाम दल के प्रतिनिधि हैं, वह धर्म को नहीं मानता, फिर एकाएक उन्हें धार्मिक अधिकारों की याद कैसे आ गई? कुछ साल पहले कर्नाटक के एक स्कूल को लेकर भी ऐसा ही विवाद हुआ था। इस विवाद को भी राजनीतिक दलों ने खूब हवा दी थी। बहुत सी महिलाएं, जो न कभी हिजाब पहनती थीं, न बुर्का, बल्कि पश्चिमी वेशभूषा में दिखाई देती थीं, उन्होंने हिजाब का समर्थन किया था। यह देखने योग्य है कि स्त्रीवाद की तमाम परिभाषाएं मजहब देखकर ही तय होती हैं। ईरान में खोमैनी के 1979 में सत्ता में आने के बाद स्त्रियों का हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके लिए सड़कों पर मोरल पुलिस घूमती है। जो स्त्रियां हिजाब पहने नहीं पाई जातीं, उन्हें भारी जुर्माना, कोड़ों और जेल की सजा दी जाती। इसी सजा के चलते 2022 में वहां महसा अमीनी की मौत हो गई थी। तब स्त्रियों में गुस्सा फूट पड़ा था। उन्होंने सिर से हिजाब उतार फेंके थे। वे प्रदर्शन करने लगीं। वहां की सरकार ने इस आंदोलन को निर्ममता से कुचला। बहुत से स्त्री-पुरुष मारे गए। खोमैनी से पहले ईरान में स्त्रियां अपनी पसंद के कपड़े पहनती थीं, लेकिन 1979 की तथाकथित क्रांति ने स्त्रियों को फिर से हिजाब और बुर्के में लपेट दिया। मामला मजहब और संस्कृति का बताकर चुप्पी साध ली गई। इसके बरक्स तुर्किये में स्त्रियों ने हिजाब के समर्थन में आंदोलन चलाया। वहां स्त्रियां हिजाब पहनने की मांग कर रही थीं। कमाल पाशा ने तुर्की में जो सुधार किए, उनमें स्त्री को पर्दे से बिल्कुल आजाद कर दिया था, लेकिन अब तुर्किये की स्त्रियों को पर्दा चाहिए। कितना विरोधाभास है। शायद इसका कारण सरकारों द्वारा लादे गए कानून होते हैं। उनका विरोध करते-करते कभी-कभी अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार ली जाती है, जैसा कि तुर्किये की स्त्रियां कर रही थीं। कुछ साल पहले हरियाणा की एक पत्रिका ने घूंघट को स्त्री अस्मिता का प्रतीक बताया था तो काफी विरोध हुआ था, लेकिन इन विरोध करने वालों ने ही हिजाब के मामले में खामोशी ओढ़ ली। आखिर यह कौन सी स्वतंत्रता की चाह है, जो मजहब और संस्कृति का बहाना बनाकर चुप हो जाती है। मेरी पसंद, मेरी आजादी की बात अब यहां तक भी आ पहुंची है कि बात-बात पर पितृसत्ता से मुक्ति की चाहत रखने वाले हिजाब या बुर्के को भी स्त्री अस्मिता का प्रतीक बताने लगे हैं। चाहे घूंघट हो या हिजाब, इसकी जिम्मेदारी स्त्रियों की ही क्यों है? पुरुषों के लिए ऐसा कोई नियम क्यों नहीं? दुनिया भर में पुरुषों ने तो अपनी ड्रेस पैंट-शर्ट कर रखी है और स्त्रियों के कपड़ों पर चौकस नजर लगी रहती है। क्या दुनिया के मजहबों और संस्कृतियों को बचाने का ठेका स्त्रियों ने ले रखा है। वे क्या करें, यह लादने वाले आप कौन? क्या इसे दोयम दर्जे की नागरिकता नहीं कहते? जब राजा राममोहन राय बंगाल में सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, तो वहां एक सती समर्थक गुट भी था। उसने स्त्रियों का एक जुलूस निकाला, जिसमें वे कह रही थीं कि वे सती होना चाहती हैं। 1987 में जब राजस्थान के दिवराला में रूपकंवर सती हो गई थी, तब एक दल की बड़ी महिला नेत्री ने बयान दिया था कि सती होना स्त्री का अपना अधिकार है।

आपको शाहबानो केस याद होगा। मामला मात्र गुजारा भत्ते का था। अदालत ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया कि उन्हें गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। बस बवाल हो गया और उस समय की केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलट दिया। बाद में शाहबानो ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला देकर गलत किया। जब उनसे पूछा गया गया कि अपने ही पक्ष में दिए फैसले को गलत क्यों बताया तो वे बोलीं-अगर मैं ऐसा न कहती, तो देश में खून की नदियां बह जातीं। कई बार लगता है कि जब से आइडेंटिटी पालिटिक्स ने लोगों के जीवन में प्रवेश किया है, तब से कई लोगों को किसी भी सुधार की बात उन्हें अपने जीवन में हस्तक्षेप लगती है।

अंतिम सांसें लेता माओवाद, आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी

आरके विज

माओवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को हाल में कुछ बड़ी सफलताएं मिली हैं। इनमें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादियों की केंद्रीय कमेटी एवं पोलित ब्यूरो के सदस्य वेणुगोपाल उर्फ भूपति उर्फ सोनू का दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्यों सहित 60 माओवादियों का आटोमेटिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कई अर्थों में महत्वपूर्ण था। इनमें से कई जोन एवं डिवीजन स्तर के और कई तकनीकी शाखा के सदस्य थे, जो हथियारों के निर्माण से लेकर उनकी मरम्मत का काम संभालते थे। भूपति दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव रहा है और आत्मसमर्पण से पहले सेंट्रल रीजनल ब्यूरो का सचिव था।

भूपति ने शांति वार्ता की पेशकश की थी, परंतु पार्टी के एकमत न होने से बात आगे नहीं बढ़ पाई। भूपति का आत्मसमर्पण माओवादियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जब भूपति ने सशस्त्र संघर्ष को रोकने की बात कही तो उत्तर-बस्तर डिवीजन, माड डिवीजन और गढ़चिरौली डिवीजन के माओवादियों ने उसका समर्थन किया। इसके बाद दंडकारण्य के माओवादी रूपेश उर्फ कोसा उर्फ सतीश, भास्कर उर्फ राजमन मड़ावी, माड की सचिव रनीता, पूर्व-बस्तर की सचिव निर्मला सहित 210 साथियों ने 17 अक्टूबर को जगदलपुर में आटोमेटिक हथियारों के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यह देश में अभी तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। वहीं, 2025 में अब तक 312 माओवादी मुठभेड़ में मारे गए तो 1,600 से अधिक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। माओवादियों के सोच में यह बदलाव अचानक नहीं आया। अगस्त 2024 में माओवादियों के पोलित ब्यूरो ने पार्टी को बचाने के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाने का निर्णय लिया था। सभी बड़े दलों और कंपनियों को छोटे टुकड़ों में बांटकर सुरक्षा बलों से बचने के प्रयास माओवादी लगातार कर रहे थे। इसके बावजूद सुरक्षा बलों के अभियानों से वे सिकुड़ते जा रहे थे। मई 2025 में पार्टी महासचिव बसवराजू अपनी मिलिट्री कंपनी के साथ नारायणपुर जिले में हुई मुठभेड़ में मारा गया। इसके बाद केंद्रीय कमेटी का सदस्य मादेम बालकृष्ण गरियाबंद में और रामचंद्र रेड्डी एवं कोसा भी मारे गए। कई माओवादियों ने विगत दिनों तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया। इनमें पूर्व माओवादी किशन जी की पत्नी पद्मावती उर्फ सुजाता, चंद्रू, विकास आदि शामिल हैं। लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित कर पुलिस को आगे बढ़ते हुए देखकर माओवादी सरगना समझ चुके हैं कि जो लड़ाई उन्होंने 1980 में दंडकारण्य में शुरू की थी, वह किसी भी हालत में जीत नहीं सकते। इसलिए, बेहतर है कि आत्मसमर्पण कर अहिंसा का रास्ता अपनाया जाए। बावजूद इसके, सोनू और रूपेश ने कहा है कि वे आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। बदली हुई स्थिति में सरकार के दो कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं। पहला यह कि क्षेत्र का समुचित विकास हो और दूसरे आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों का समुचित पुनर्वास।

सरकार को चाहिए कि वह ऐसी समस्त सामाजिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करे, जिन्हें आधार बनाकर माओवादियों ने ग्रामीणों में पैठ बनाई थी। विकास की योजना 'नियद नेल्लानार' (आपका अच्छा गांव) जैसी योजनाओं का विस्तार केवल सुरक्षा कैंपों की पांच किलोमीटर की परिधि तक सीमित न रखते हुए ऐसे पूरे इलाकों में कर दें, जहां माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। शिक्षा के आश्रम बनाने, स्वास्थ्य सेवा के लिए अस्पताल या डिस्पेंसरी बनाने की योजनाओं को शीघ्र मूर्त रूप देना होगा, क्योंकि आदिवासियों के लिए वनोपज जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन है। उनके उचित दाम एवं उनकी प्रोसेसिंग के लिए कुछ योजनाएं लागू करने पर भी विचार करना होगा। सड़कों का निर्माण और मोबाइल टावर्स भी लगाए जाएं। ऐसे विकास कार्यों को क्रियान्वित करने में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। सरकार यह निगरानी भी करे कि आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों को पुनर्वास नीति का लाभ शीघ्र मिले। उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देकर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने होंगे। यह सब करने के बाद भी उन इलाकों पर सुरक्षा बलों को नजर बनाए रखनी होगी, जहां माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार बसवराजू के मरने के बाद माओवादी अपने नए महासचिव का चुनाव नहीं कर पाए हैं। दंडकारण्य के नए सचिव का भी चुनाव नहीं हुआ है। यही कारण है कि केंद्रीय कमेटी एकजुट होकर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है और सभी डिवीजन अपनी-अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर युद्धविराम की घोषणाएं कर रही हैं। हालांकि तेलंगाना स्टेट कमेटी ने युद्ध जारी रखने की बात कही है, परंतु वह न केवल स्वयं कमजोर स्थिति में है, बल्कि उसके बड़े सदस्य भी राज्य से बाहर शरण लिए हुए हैं। पूर्व महासचिव गणपति, केंद्रीय कमेटी सदस्य संग्राम, गणेशन्ना, हेमंत बिसरा आदि की तरफ से भी कोई बयान जारी नहीं हुआ है। अभी पूरी माओवादी पार्टी नेतृत्वविहीन है तो भारत सरकार अगले वर्ष 31 मार्च तक माओवादियों के उन्मूलन को लेकर प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय के अनुसार देश में माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 11 रह गई है, जिनमें से केवल तीन जिले ही अत्यंत प्रभावित हैं। इन 11 जिलों में से सात छत्तीसगढ़ के हैं। इनमें नारायणपुर और कांकेर में लगभग समस्त माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। गरियाबंद जिले के माओवादियों ने भी आत्मसमर्पण की बात कही है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर दंडकारण्य के लगभग सभी माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब केवल माओवादियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रमुख देवजी के अलावा, मिलिट्री बटालियन का प्रमुख माड़वी हिड़मा और दंडकारण्य कमेटी के कुछ सदस्य शेष हैं, जो शायद अभी आत्मसमर्पण करने या युद्ध जारी करने को लेकर असमंजस में हैं। संभव है कि वे भी सोनू और रूपेश की तरह परिस्थितियों को देखते हुए जल्द ही मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला करें। अगर ऐसा नहीं होता तो भी माओवादी पार्टी केवल एक औपचारिकता ही बनकर रह जाएगी।

लग्जरी लोकपाल कैसे बनेंगे भ्रष्टाचार विरोधी और सार्वजनिक जीवन में शुचिता की मिसाल?

नीरज कुमार दुबे

भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त और स्वतंत्र संस्था के रूप में लोकपाल का गठन किया गया था। उद्देश्य स्पष्ट था– सत्ता के गलियारों में फैले भ्रष्टाचार पर नकेल कसना और सार्वजनिक जीवन में शुचिता को संस्थागत रूप देना। परंतु विडंबना देखिए कि आज वही संस्था, जिसके गठन से आम जनता ने पारदर्शिता और सादगी की उम्मीद की थी, अब अपनी छवि पर सवालों के घेरे में है। वजह है लोकपाल कार्यालय की ओर से सात बीएमडब्ल्यू 330Li एम स्पोर्ट कारों की खरीद के लिए जारी किया गया करोड़ों रुपये का निविदा आमंत्रण। यह कदम न केवल नैतिक दृष्टि से सवाल खड़े करता है, बल्कि उस वैचारिक आधार को भी कमजोर करता है जिस पर लोकपाल की इमारत खड़ी की गई थी। जब संस्था का गठन हुआ था, तब लोग उम्मीद कर रहे थे कि लोकपाल सत्ताधारी वर्ग की जवाबदेही तय करेगा। लेकिन आज, जब लोकपाल खुद विलासिता की राह पर अग्रसर दिखाई देता है, तो यह प्रश्न उतना स्वाभाविक है कि क्या यह वही संस्था है जिसके लिए देश की जनता सड़कों पर उतरी थी? हम आपको बता दें कि लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी टेंडर में कहा गया है कि ये वाहन संस्थान के अध्यक्ष एवं सदस्यों के उपयोग हेतु होंगे। सवाल यह है कि एक ऐसी संस्था, जिसे सार्वजनिक धन की शुचिता पर नजर रखनी चाहिए, वह खुद इतने महंगे वाहनों की खरीद को कैसे उचित ठहरा सकती है? जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी सामान्य सिडान कारों से कार्य कर सकते हैं, तब लोकपाल के लिए करोड़ों की जर्मन गाड़ियाँ क्यों आवश्यक हैं? कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने इसी तर्क को रेखांकित करते हुए पूछा है, जब सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश साधारण गाड़ियों में चलते हैं, तो लोकपाल को बीएमडब्ल्यू की क्या आवश्यकता है?– यह प्रश्न केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि नैतिक और प्रशासनिक संवेदनशीलता का भी है। जनता के कर के पैसे से बनी संस्थाओं की जवाबदेही जनता के प्रति होती है। परंतु जब ऐसी संस्थाएँ अपने ही संसाधनों को विलासिता में व्यय करने लगें, तो यह संकेत है कि व्यवस्था में आत्ममुग्धता प्रवेश कर चुकी है। यह बात भी विचारणीय है कि अब तक लोकपाल ने कितने बड़े भ्रष्टाचार मामलों में कार्रवाई की है? वर्ष 2014 से लेकर अब तक, इस संस्था की उपलब्धियाँ नगण्य रही हैं। कई राज्यों में लोकायुक्त सक्रिय हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकपाल की भूमिका अधिकतर औपचारिक ही दिखी है। ऐसे में करोड़ों रुपये खर्च कर विलासिता का यह प्रदर्शन, न केवल नैतिक असंगति है, बल्कि जनता के विश्वास का भी दुरुपयोग है। विपक्षी नेताओं के अलावा नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने भी इस निविदा पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि लोकपाल को यह टेंडर रद्द कर मेक इन इंडिया की भावना के अनुरूप महिंद्रा या टाटा के इलेक्ट्रिक वाहनों का चयन करना चाहिए था। यह सुझाव केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि पर्यावरणीय और सांस्कृतिक दृष्टि से भी सार्थक है। जब देश आत्मनिर्भर भारत और ईवी मिशन की दिशा में अग्रसर है, तब विदेशी विलासिता को अपनाना आत्मनिर्भरता की भावना के विपरीत है। देखा जाये तो लोकपाल जैसी संस्था का नैतिक बल उसकी सादगी और ईमानदारी में निहित होता है। यदि वही संस्था आम जनता से कटकर अभिजात्य मानसिकता अपनाने लगे, तो उसका नैतिक अधिकार स्वतः कमजोर हो जाता है। यह केवल एक टेंडर का मामला नहीं है; यह उस सोच का प्रतीक है जिसमें सेवा की जगह सुविधा ने ले ली है। बहरहाल, लोकपाल के गठन का मकसद भ्रष्टाचार से लड़ना था, न कि जनसंसाधनों से विलासिता का आनंद लेना। इस प्रकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि संस्थाएँ अपने आदर्शों से विचलित हों, तो वह जनता की नजर में अपनी विश्वसनीयता खो देती हैं। लोकपाल को चाहिए कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करे, निविदा को रद्द करे और एक बार फिर उस सादगी की राह पर लौटे, जिसकी प्रेरणा से उसका जन्म हुआ था। सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार केवल धन के लेन-देन से नहीं, बल्कि मानसिकता से शुरू होता है। जब शुचिता की प्रतीक संस्था ही विलासिता की प्रतीक बन जाए, तो यह केवल विडंबना नहीं, बल्कि चेतावनी है– उस आदर्श की, जो धीरे-धीरे धुंधला पड़ता जा रहा है।

मोदी-ट्रंप की वार्ता, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता होने के आसार

दीवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शुभकामनाओं का आदान-प्रदान होने के साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता होने के आसार बढ़ना एक शुभ संकेत है। माना जा रहा है कि दोनों देशों में अगले माह व्यापार समझौता हो सकता है। उसके पहले मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं में भेंट भी हो सकती है। व्यापार समझौता होने को लेकर आसार इसलिए बढ़ गए हैं, क्योंकि एक तो दोनों नेताओं ने वैश्विक सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद और रणनीतिक साझेदारी समेत व्यापार वार्ता पर भी बात की और दूसरे, अमेरिकी राष्ट्रपति अपने इस दावे से पीछे हटते दिखे कि भारत रूस से तेल खरीद बंद करने पर सहमत हो गया है। इसके बजाय उन्होंने यह कहा कि भारत रूस से अधिक तेल नहीं खरीदेगा। दोनों बातों में अंतर है। यह अंतर समझौते की संभावनाएं पैदा करने वाला है। ट्रंप की बदली भाषा से यह संकेत मिलता है कि वे रूस से तेल खरीद के मामले में बीच का कोई रास्ता निकालने और भारत को रियायत देने के इच्छुक हैं। उन्हें ऐसा करना ही होगा, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता। भारत यह भी नहीं कर सकता कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो कुछ कहें, वह उसे आंख मूंदकर मान ले। संप्रभु राष्ट्र भारत को अपने हितों की रक्षा करने और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने का उतना ही अधिकार है, जितना अमेरिका को। शायद ट्रंप को यह समझ आने लगा है कि भारत को उस तरह नहीं झुकाया जा सकता, जैसे उन्होंने कई देशों को झुकाया है। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के मनगढ़ंत दावों और बड़बोले बयानों का जवाब कूटनीतिक भाषा में देने की जो रणनीति अपनाई है, वही उनके अड़ियल रवैये से पार पाने का सही तरीका है। भारत को उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देने के स्थान पर कूटनीतिक कौशल का सहारा लेकर अपने हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत की पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि उसके अनुकूल अमेरिका से कोई व्यापार समझौता हो जाए। एक बार ऐसा समझौता हो जाए तो संबंधों के पटरी पर आने में अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसे भी भारत के सहयोग की आवश्यकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि यदि अमेरिका के साथ शीघ्र व्यापार समझौता हमारी प्राथमिकता है तो अमेरिका को भी अपने अंतरराष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए हमारा साथ चाहिए। वास्तव में दोनों देशों के हित एक-दूसरे से संपर्क-सहयोग में ही जुड़े हैं। तथ्य यह भी है कि आज अमेरिका भारत की अनदेखी करने में समर्थ नहीं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने के साथ देश का अंतरराष्ट्रीय कद भी बढ़ा रही है।

हर कॉल के बाद झूठा दावा करने वाले ट्रंप से क्या मोदी को आसियान सम्मेलन में मिलना चाहिए?

नीरज कुमार दुबे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसने न केवल कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि यह भी दिखाया है कि वाशिंगटन की राजनीति में भारत का उल्लेख प्रायः घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दीपावली समारोह के दौरान दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत रूस से बहुत अधिक तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने कहा, –मोदी ने बताया है कि भारत अब रूस से बहुत ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा। वे भी चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध समाप्त हो। वहीं बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''राष्ट्रपति ट्रंप आपके फोन करने और दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद। रोशनी के इस पर्व पर दोनों महान लोकतंत्र दुनिया को आशा की किरण दिखाते रहें और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ एकजुट रहें।''गौर करने वाली बात यह है कि मोदी और ट्रंप के बीच 16 सितंबर के बाद से फोन पर हुई यह तीसरी बातचीत है जिसकी सार्वजनिक रूप से जानकारी दी गयी है। सार्वजनिक जानकारी में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे यह प्रदर्शित होता हो कि रूसी तेल को लेकर दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत हुई तो वहीं ट्रंप ने अपने बयान में रूसी तेल खरीद को लेकर फिर से अपना पुराना दावा दोहरा दिया है। हम आपको बता दें कि मंगलवार रात को ट्रंप ने दिवाली समारोह का आयोजन किया था जिसमें अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा और कई प्रमुख भारतीय मूल के व्यापारिक नेता शामिल हुए। समारोह में अपने संबोधन में ट्रंप ने फिर से अपना यह दावा दोहराया कि भारत, रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा।

देखा जाये तो यह दावा न तो भारत सरकार की किसी आधिकारिक घोषणा में परिलक्षित होता है और न ही वैश्विक तेल बाजार के आँकड़े इसे पुष्ट करते हैं। तेल व्यापार जगत के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की रूसी तेल खरीद में कोई विशेष कमी नहीं आई है; अधिकांश सौदे पहले से तय अनुबंधों के अंतर्गत चल रहे हैं। देखा जाये तो ट्रंप के इस वक्तव्य के दो प्रमुख पहलू हैं– पहला, यह कि वह आश्वासन का दावा कर रहे हैं, जबकि भारत ने ऐसा कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। दूसरा, ट्रंप ने खुद अपने पहले के दावे को थोड़ा नरम करते हुए कहा कि भारत पूरी तरह नहीं, काफी कम तेल खरीदेगा। यह बदलाव संकेत देता है कि या तो उन्हें पहले गलत जानकारी दी गई थी, या वे जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं जो घरेलू राजनीतिक संदेशों के लिए उपयोगी हों। दूसरी ओर, भारत ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि उसकी ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हित से संचालित होती है और जब तक पश्चिमी प्रतिबंध भारत पर लागू नहीं है, वह सस्ते रूसी कच्चे तेल का आयात जारी रखेगा। ऐसे में ट्रंप के बयान का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं दिखता। वैसे यह पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का हवाला देते हुए भ्रामक या

अतिशयोक्तिपूर्ण दावा किया हो। ट्रंप की राजनीति में सुपर डीलमेकर की छवि बनाये रखना आवश्यक है। वह हर अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल को एक बड़ी डील के रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि अमेरिकी मतदाताओं को लगे कि वह विश्व मंच पर अमेरिका फर्स्ट नीति को सफल बना रहे हैं। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के साथ मित्रवत संबंध उनके लिए प्रचार का सबसे आसान माध्यम है– क्योंकि वहां का प्रवासी भारतीय समुदाय अमेरिकी चुनावी परिदृश्य में एक प्रभावशाली वर्ग बन चुका है। उधर, प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह स्थिति नाजुक है। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक संबंध गहरे हो रहे हैं– क्वॉड, इंडो-पैसिफिक और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में दोनों देश निकटता बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति बार-बार ऐसे फर्जी या अधूरे दावे करते हैं जो भारत की संप्रभु नीति पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं, तो दिल्ली की प्रतिक्रिया केवल शालीन मौन तक सीमित नहीं रह सकती।

भारत का विदेश मंत्रालय अब तक ट्रंप के बयानों पर नो कमेंट नीति अपनाता आया है, किंतु इससे यह जोखिम रहता है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिकी दावा धीरे-धीरे स्वीकार्य धारणा बन सकता है। इसीलिए, भारत को स्पष्ट रूप से यह संकेत देना चाहिए कि ऊर्जा नीति या रूस से व्यापार जैसे निर्णय किसी बाहरी दबाव के अधीन नहीं लिए जाते। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप के ऐसे भ्रामक दावों के बीच मोदी का उनसे मिलना ठीक होगा?

हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की संभावित भेंट अगले सप्ताह मलेशिया में होने वाले आसियान सम्मेलन के दौरान हो सकती है। यह बैठक औपचारिक रूप से तय नहीं है, किंतु अगर होती है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या मोदी को ऐसे नेता से मिलना चाहिए जो हर बार बातचीत को घरेलू प्रचार का हथियार बना देता है? देखा जाये तो कूटनीति में संबंध बनाए रखना और गरिमा बचाए रखना दोनों समान रूप से आवश्यक है।

भारत अमेरिका से संबंध तोड़ नहीं सकता– लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि वह किसी भी मंच पर अपनी नीति को सहभागी की तरह प्रस्तुत करे, उपसंहारक की तरह नहीं। मोदी सरकार को इस भेंट को औपचारिक संवाद के स्तर तक सीमित रखना चाहिए और किसी भी संयुक्त बयान में ऐसे शब्दों से बचना चाहिए जिन्हें ट्रंप बाद में अपने राजनीतिक लाभ के लिए तोड़-मरोड़ सकें। इसमें कोई दो राय नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की शैली त्वरित, आत्म-केन्द्रित और प्रचारमुखी है।

वह हर वार्ता को शो में बदल देते हैं। भारत जैसे परिपक्व लोकतंत्र के लिए ऐसे प्रदर्शनों में भागीदार बनना न तो आवश्यक है, न लाभकारी। भारत को अपने हित में, अपने स्वर में और अपने तथ्यों के आधार पर बोलना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के दीपावली डिप्लोमेसी में शामिल होना तो ठीक है, पर उनके फर्जी तेल-सत्य के खेल में नहीं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर सबसे बड़ी शक्ति वही होती है जो अपने शब्दों पर टिकी रह सके और भारत को यही दिखाना होगा कि उसकी नीतियाँ किसी «ट्रंप टेलीफोन कॉल» से नहीं, बल्कि उसकी अपनी ऊर्जा, रणनीति और आत्मविश्वास से संचालित होती हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने कल्पना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पीपलवाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/08862)

दिल्ली-एनसीआर में दमघोंटू हवा का कहर, लगातार आज भी 400 के पार एक्यूआई

नई दिल्ली । दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। जिसकी वजह से हवा की गुणवत्ता पर बहुत खराब असर पड़ा है। दीपावली के तीन दिन बाद एक्यूआई का स्तर 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता का रेड जोन में होना एक गंभीर चेतावनी है। भले ही पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन पीएम 2.5 के बढ़ते स्तर ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आकंड़ों के मुताबिक, दिल्ली के आनंद विहार में गुरुवार सुबह एक्यूआई 428 दर्ज किया गया। यह आंकड़ा %गंभीर% श्रेणी में आता है, जो वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को दर्शाता है। अक्षरधाम के आसपास 350, इंडिया गेट और इसके आसपास के इलाकों में 353, एम्स में 342 एक्यूआई दर्ज किया गया है। बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 353 दर्ज किया गया, जो रेड जोन यानी हवा की बेहद खराब श्रेणी में आता है। कई जगहों पर एक्यूआई 400 को पार कर गया, जो गंभीर चिंता का विषय है। मंगलवार को भी एक्यूआई 351 दर्ज किया गया था, जबकि बुधवार सुबह ITO का AQI 353 रहा। गुरुवार सुबह गाजियाबाद में 175, नोएडा में 193 और ग्रेटर नोएडा में 183 एक्यूआई दर्ज किया गया है। बीते बुधवार को ग्रेटर नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 308 दर्ज हुआ। ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 292 दिन पहले रेड जोन में रहा था। वहीं बुधवार को नोएडा का एक्यूआई भी 24 घंटे में 10 अंक बढ़कर 330

पहुंच गया है। दोनों शहरों में पूरे दिन स्मॉग छाया रहा। जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई और आंखों में जलन की शिकायत बनी रही। निवासियों का आरोप है कि शहर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी से प्रदूषित हुई हवा में बारूद का धुआं घुला रहा। मंगलवार रात सबसे अधिक 333 एक्यूआई दर्ज किया गया। वहीं, बुधवार को दिन में अधिकतम एक्यूआई 305 पहुंच गया। बड़ी बात यह है कि वायु प्रदूषण में धूल के कणों की मात्रा अधिक होने से पीएम 2.5 का स्तर अधिक बना हुआ है, जो बुधवार को भी 301 पर दर्ज हुआ जबकि, पीएम 10 का स्तर 192 पर दर्ज हुआ। इस कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वहीं, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप का दूसरा चरण जिले में लागू कर दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिवाली के बाद दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई है। शहर में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम 2.5) का स्तर पिछले पांच वर्षों में सबसे खराब स्थिति में पहुँच गया है। दिवाली के तुरंत बाद, 24 घंटे के भीतर पीएम 2.5 की औसत सांद्रता 488 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुँच गई, जो त्योहार से पहले के 156.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के स्तर से तीन गुना से भी अधिक है। 2021 से 2025 तक के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि दिवाली की रात और अगली सुबह पीएम 2.5 की भागीदारी लगातार बढ़ी है। वर्ष 2025 में दिवाली के बाद 488 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की रीडिंग दर्ज की गई, जो 2021 के बाद से उच्चतम प्रदूषण स्तर को दर्शाता है। पिछले वर्षों में, दिवाली के बाद औसत पीएम 2.5 का स्तर इस प्रकार रहा: 2021 में 163.1 से बढ़कर 454.5, 2022 में 129.3 से बढ़कर 168, 2023 में 92.9 से बढ़कर 319.7, और 2024 में 204 से बढ़कर 220 रहा। इस बार पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 77 फीसदी की कमी आई है। क्लाइमेट ट्रेंड्स के अनुसार, यह गिरावट मुख्य रूप से बाढ़ और फसल चक्र में देरी के कारण हुई। 1 से 12 अक्टूबर के बीच, जब पराली जलाने की घटनाएं अपने चरम पर होती हैं, तब भी दिल्ली के पीएम 2.5 स्तर में 15.5 फीसदी की कमी दर्ज की गई। हालांकि, इस कमी के बावजूद, अन्य स्रोतों से होने वाले प्रदूषण ने हवा की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

दम फूलने के साथ रात की नींद भी उड़ा रहा प्रदूषण, अस्थमा-दमा मरीजों की बढ़ी

दिल्ली । राजधानी में बढ़ता प्रदूषण लोगों की रात की नींद भी उड़ा रहा है। अलग-अलग अस्पतालों की ओपीडी में सांस फूलने, खांसी, सिरदर्द, आंखों में जलन, तनाव व नींद न आने सहित कई दूसरे लक्षण लेकर लोग अस्पतालों में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही, अस्थमा, दमा व सीओपीडी मरीजों की दवा की खुराक भी प्रदूषण के कारण बढ़ गई है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल के मेडिसिन विभाग में प्रो. डॉ. कुलदीप कुमार ने बताया कि सांस संबंधी परेशानी को लेकर अस्पताल की ओपीडी में 10-20 फीसदी मरीज बढ़ गए हैं। एलर्जी ब्रोनकाइटिस की समस्या मरीजों में आमतौर पर देखने को मिल रही है। इसमें मरीज को लगातार खांसी, सांस लेने में तकलीफ, छाती में जकड़न व घरघराहट की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण अस्थमा, दमा और सीओपीडी मरीजों को दवा की खुराक बढ़ानी पड़ रही है। पहले जो मरीज दिन में दो बार दवा लेता था अब उसे चार-पांच बार दवा देने का परामर्श दिया जा रहा है। मरीज नींद न आने की परेशानी भी बता रहे हैं।

हर उम्र का व्यक्ति उपचार के लिए आ रहा है। हार्ट और किडनी के मरीजों की परेशानी भी बढ़ गई है। इधर, दिल्ली सरकार के सबसे बड़े लोकनायक अस्पताल में अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक एवं मीडिया समन्वयक डॉ. प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि प्रदूषण के कारण ओपीडी में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। बच्चे और बुजुर्ग सांस संबंधी परेशानी को लेकर पहुंच रहे हैं। खांसी की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। अस्पताल प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के बढ़ते मामलों के प्रति पूरी तरह सतर्क है। प्रदूषण के बढ़ने पर हृदय संबंधी मरीजों में उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा और स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉ. बीएल चौधरी के निर्देशन में रेस्पिरेटरी और इमरजेंसी टीम 24 घंटे अलर्ट मोड में है। ऑक्सीजन, नेबुलाइजर और आवश्यक दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लोगों से अपील है कि वह प्रदूषण नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभाएं।

बिहार के चार मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मुठभेड़ में ढेर, संयुक्त अभियान में दिल्ली पुलिस को सफलता

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस ने बिहार के चार मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और बिहार पुलिस के संयुक्त अभियान में रोहिणी में हुई मुठभेड़ में बिहार के चार मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक्स में उस जगह के दृश्य जारी किये हैं जहां रात 2.20 बजे चार आरोपियों और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम के बीच गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में बिहार के रंजन पाठक (25), बिमलेश महतो (25), मनीष पाठक (33) और अमन ठाकुर (21) मारे गए। रंजन पाठक, बिमलेश महतो और मनीष पाठक सीतामढ़ी, बिहार के रहने वाले थे और अमन ठाकुर करवाल नगर, दिल्ली का रहने वाला था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बिहार पुलिस के साथ रोहिणी में एक मुठभेड़ के दौरान बिहार के कुख्यात रंजन पाठक गैंग के चार सदस्यों को गोली मार दी। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले गैंग सदस्यों द्वारा किसी बड़ी

आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने की योजना बनाई थी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में जाल बिछाया। चारों पर बिहार में कई मामले दर्ज हैं। जिसमें हत्याएं और सशस्त्र डकैती शामिल हैं। आगे की जांच जारी है। डीसीपी क्राइम ब्रांच डीसीपी संजीव यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर रोहिणी में एक मुठभेड़ के दौरान बिहार के कुख्यात रंजन पाठक गिरोह के चार सदस्यों को मार गिराया। मुठभेड़ सुबह करीब 2:20 बजे हुए। इस विशेष खुफिया सूचना के आधार पर गिरोह के सदस्य आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आगे कहा कि दिल्ली पुलिस अपराध शाखा और बिहार पुलिस की एक संयुक्त टीम ने इलाके में जाल बिछाया। जब पुलिस दल ने संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद संक्षिप्त लेकिन भीषण गोलीबारी हुई। चारों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए और उन्हें रोहिणी के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि मारे गए लोगों की पहचान रंजन पाठक, बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश साहनी (25), मनीष पाठक (33), अमन ठाकुर (21) के रूप में हुई है। चारों बिहार में कई हत्याओं और सशस्त्र डकैती सहित कई मामलों में वांछित थे। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। फोरेंसिक और अपराध स्थल जांच टीमों को बुलाया गया। आगे की जांच जारी है।

एससी-एसटी कानून बैंक के बंधक अधिकारों में नहीं डालता बाधा, अदालत ने की यह टिप्पणी

दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल किसी बैंक को उसके वैध बंधक अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। कानून के ये प्रावधान, एससी-एसटी समुदाय के लोगों की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा या बेदखली रोकने से संबंधित हैं। जस्टिस सचिन दत्ता ने यह टिप्पणी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से एक्सिस बैंक, उसके प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाते हुए की। जस्टिस दत्ता ने 16 अक्तूबर को पारित आदेश में कहा, मामले में अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(एफ) और (जी) लागू नहीं होती हैं क्योंकि याचिकाकर्ता के बंधक अधिकार के

प्रयोग को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति ने एससी-एसटी कानून का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए आयोग के सामने अभ्यावेदन दिया था। आयोग ने बैंक के एमडी और सीईओ को पेश होने का आदेश दिया था। कानून की धारा 3(1)(एफ) एससी/एसटी समुदाय के किसी सदस्य की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करने या खेती करने पर दंड का प्रावधान करती है, जबकि धारा 3(1)(जी) किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से गलत तरीके से बेदखल करने की सजा से संबंधित है। अदालत के समक्ष दायर याचिका के अनुसार, एक्सिस बैंक ने 2013 में महाराष्ट्र के वसई की संपत्ति गिरवी रखकर सनदेव अप्लायंसेज लि. को 16.69 करोड़ रुपये का लोन दिया था। उधार लेने वाले के भुगतान न करने पर, 2017 में खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया और बैंक ने गिरवी रखी संपत्ति को अपने अधिकार में लेने के लिए कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए आदेश पर रोक लगा दी कि आयोग के समक्ष लंबित कार्यवाही उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने समन जारी कर बैंक के एमडी और सीईओ को उसके समक्ष उपस्थित होने को कहा था। हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग ने समन जारी करने के पीछे कोई तर्क दर्ज नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले साल 5 फरवरी के लिए निर्धारित कर दी।

जहरीली हवा में सांस लेना दूभर, रेड जोन में दिल्ली

दिल्ली । देश की राजधानी वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। जहरीली हवा ने सांस लेना भी दूभर कर दिया है। ऐसे में बच्चों व बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 353 दर्ज किया गया जो रेड जोन यानी हवा की बेहद खराब श्रेणी है। कई जगहों पर एक्यूआई 400 को पार कर गया। मंगलवार को एक्यूआई 351 दर्ज किया गया था और आज सुबह ITO का AQI रहा 353 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का पूर्वानुमान है कि शनिवार तक हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी। इस कारण सांस के मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, लोगों को आंखों में जलन हो सकती है। बुधवार को अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहराई 2500 मीटर रही। इसके अलावा वेंटिलेशन इंडेक्स 6000 मीटर प्रति वर्ग सेकंड रहा। नेहरू नगर समेत तीन इलाकों में एक्यूआई गंभीर और 33 इलाकों में एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाली के बाद दिल्ली की एयर क्वालिटी तेजी से खराब हुई है। शहर के पार्टिकुलेट मैटर (पीएम 2.5) का लेवल पांच साल में सबसे ज्यादा खराब हो गया है।

त्रिपुरा में 24 घंटे के बंद से जनजीवन अस्त-व्यस्त, एम्बुलेंस रोकी, कानून व्यवस्था पर सवाल

नई दिल्ली । त्रिपुरा सिविल सोसाइटी ने गुरुवार (23 अक्तूबर) को 24 घंटे के बंद का आह्वान किया है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) के विधायक रंजीत देबबर्मा ने कहा कि बंद को लागू करने के लिए राज्य भर में 25 स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए जाएँगे। अगरतला के प्रमुख स्थानों, जैसे सर्किट हाउस, उत्तरी द्वार और राज्य विधानसभा, पर भी बैरिकेड्स लगाए जाएँगे। देबबर्मा ने कहा, ‘यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है जहाँ सभी वर्ग के लोग राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर बंद में शामिल होंगे। हम अपनी माँगों के समर्थन में इस बंद को शांतिपूर्ण ढंग से सफल बनाने के लिए तैयार हैं। टिपरासा सिविल सोसाइटी द्वारा आहूत 24 घंटे के राज्यव्यापी बंद के बाद आज त्रिपुरा में व्यापक तनाव और व्यवधान देखा गया। कथित तौर पर टिपरा मोथा कार्यकर्ताओं द्वारा समर्थित इस आंदोलन के कारण नाकाबंदी, विरोध और प्रशासनिक निष्क्रियता की कई घटनाएँ हुईं, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया और राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। बरमुरा हिल्स में, तेलियामुरा उप-मंडल अस्पताल की एक एम्बुलेंस को कथित तौर पर बंद समर्थकों ने रोक दिया, जिससे उसे अपने गंतव्य तक पहुँचे बिना ही अस्पताल लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों ने इस कृत्य की निंदा करते हुए इसे अमानवीय बताया, जबकि पर्यवेक्षकों ने मुख्यमंत्री द्वारा सामान्य स्थिति बनाए रखने के बार-बार निर्देशों के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता की आलोचना की। मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने बंद पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि त्रिपुरा में जनजीवन सामान्य रहेगा और सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर आना होगा। हालांकि, कई कर्मचारी सुबह से ही पुलिस प्रतिबंधों और सड़क अवरोधों के बीच सड़कों पर असहाय होकर फंसे हुए थे। नागरिकों ने आरोप लगाया कि पुलिस, सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के बजाय, वाहनों और यात्रियों को लंबे रास्तों से, खासकर अगरतला के उत्तरी गेट क्षेत्र के पास, डायवर्ट कर रही थी। इस बीच, बंद समर्थकों ने जिरानिया के बिरगुदास इलाके में अगरतला-करीमगंज एक्सप्रेस रोक दी। टिपरासा सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर रेलवे पटरियों पर विरोध प्रदर्शन किया। इससे रेल यातायात अस्थायी रूप से ठप हो गया और आसपास के इलाकों में तनाव पैदा हो गया। खोवाई के बेलछारा इलाके और शांतिरबाजार उपखंड से भी खबरें आईं, जहाँ बंद समर्थकों ने धरना दिया, बाजार बंद करवाए और परिवहन ठप कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने इन दृश्यों को त्रिपुरा में पहले के राजनीतिक आंदोलनों के दौरान हुई अशांति की याद दिलाते हुए बताया। आलोचकों ने आरोप लगाया कि नागरिक समाज द्वारा आहूत इस बंद को टिपरा मोथा का मौन समर्थन प्राप्त था और राज्य मशीनरी के कुछ हिस्सों ने अप्रत्यक्ष रूप से इसमें मदद की, जबकि पुलिस केवल मूकदर्शक बनी रही। सोशल मीडिया पर विपक्षी आवाजों ने भाजपा के प्रमुख संगठनों की चुप्पी पर सवाल उठाए और प्रशासन पर दोहरे मापदंड अपनाने और बंद की सफलता सुनिश्चित करने के लिए गुप्त सहयोग करने का आरोप लगाया।

मुंबईः जोगेश्वरी वेस्ट में जेएमएस बिजनेस सेंटर में लगी भीषण आग, राहत और बचाव अभियान जारी

मुंबई मुंबई के जोगेश्वरी पश्चिम इलाके में जेएमएस बिजनेस सेंटर में गुरुवार को भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमारत में आग सुबह करीब 11 बजे का आसपास लगी थी। आग लगने के बाद इमारत के अंदर कई लोग फंस गए थे, हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार सुबह मुंबई के पश्चिमी उपनगर जोगेश्वरी में एक बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लग गई। उन्होंने बताया कि गांधी स्कूल के पास जेएमएस बिजनेस सेंटर में सुबह करीब 10.50 बजे लगी आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि इमारत के दूसरे हिस्से में 10-15 लोग फंसे हुए हैं। लेकिन वे सुरक्षित हैं। बचाव अभियान जारी है। एक दमकल अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए कम से कम 12 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर विभिन्न एजेंसियों को तैनात किया गया है। आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल पाई है, इसकी जांच की जा रही है।

छठ महापर्व पर रेलवे की मेगा तैयारी, 12,000 विशेष ट्रेनें और कड़ी सुरक्षा के साथ बिहार रवाना

नई दिल्ली । छठ पूजा की तैयारियाँ जोरों पर है और भारतीय रेलवे महाराष्ट्र में त्योहारी भीड़ को संभालने के लिए कमर कस रहा है। सूर्य देव को समर्पित यह त्योहार, जो अगले हफ्ते मनाया जाएगा, बस कुछ ही दिन दूर है। भारतीय रेलवे ने यात्री यातायात में अनुमानित वृद्धि को देखते हुए व्यवस्थाएँ की हैं। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बिहार में पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) जोन के सभी रेलवे स्टेशनों पर व्यापक व्यवस्था की गई है। ईसीआर के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने जोर देकर कहा कि रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता यात्रियों के लिए सुगम आगमन और प्रस्थान सुनिश्चित करना है, साथ ही किसी भी अप्रिय घटना को रोकना भी है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, और कहा कि असली चुनौती तब आएगी जब लोग छठ पर्व के बाद लौटेंगे। उन्होंने कहा, इस साल छठ विशेष ट्रेनों की संख्या 7,500 से बढ़कर 12,000 कर दी गई है। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में लोगों के छठ मनाने के लिए बिहार आने की उम्मीद है। उनके आगमन की तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। हालाँकि, असली चुनौती तब आएगी जब वे त्योहार के बाद अपने कार्यस्थलों पर लौटेंगे। उन्होंने आगे कहा, वापसी के लिए समय कम है, लेकिन उसके लिए भी तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं। सिंह के अनुसार, सभी प्रमुख रेलवे टर्मिनलों पर आज तक होल्डिंग एरिया तैयार हो जाएँगे। इसके बाद, पूर्व मध्य रेलवे व्यवस्थाओं का परीक्षण करने के लिए एक 'ड्रेस रिहर्सल' करेगा। सिंह ने कहा कि पाटलिपुत्र रेल परिसर से केंद्रीकृत निगरानी की जाएगी। विभिन्न स्टेशनों पर रेल यातायात की निगरानी के लिए मंडल कार्यालयों में भी इसी तरह की व्यवस्थाएँ स्थापित की गई हैं। इस वर्ष, जोन में विशेष ट्रेनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। सिंह ने कहा कि इससे यात्रियों को केवल ट्रेन से ही दूर-दराज के स्थानों तक पहुँचने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, अगर बड़ी संख्या में बिना आरक्षण वाले लोग आते हैं, तो प्रमुख टर्मिनलों से कई अनारक्षित ट्रेनें चलाई जाएँगी। त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत किया जाएगा। सिंह ने कहा, हमने छठ के दौरान और उसके बाद सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने का दृढ़ संकल्प लिया है। रेलवे कर्मी इस कार्य में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

जुबली हिल्स उपचुनावः 211 में से 81 उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार, 11 नवंबर को होगा मतदान

तेलंगाना हैदराबाद में जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए 81 उम्मीदवारों के नामांकन को चुनाव आयोग ने स्वीकार किया। वहीं 130 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज कर दिए गए। बता दें कि कुल 211 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे। इनमें से कुछ ने नामांकन के दो सेट दाखिल किए। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि बुधवार को शुरू हुई नामांकन पत्रों की जांच के दौरान केवल 81 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अक्तूबर है। जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव 11 नवंबर को होगा और मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। इस वर्ष जून में बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ की हार्ट अटैक से मृत्यु के कारण यह उपचुनाव जरूरी हो गया है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने वी नवीन यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया, जबकि विपक्षी बीआरएस ने दिवंगत विधायक की विधवा मगंती सुनीता को मैदान में उतारा। भाजपा ने लंकाला दीपक रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि पार्टी जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव का समर्थन करेगी। इस उपचुनाव में ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें लगाना, एआई आधारित निगरानी का उपयोग और गड़बड़ी रोकने के लिए संवेदनशील मतदान केंद्रों की जीपीएस आधारित निगरानी जैसे नए उपाय लागू होंगे।

दामाद के लड़कियों से थे संबंध ..., निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष की पत्नी की मिली लाश

झांसी । झांसी में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव कुमार निषाद की पत्नी नीलू रायकवार का शव संदिग्ध अवस्था में बुधवार को कमरे के अंदर फंदे से झूलता मिला। पति से विवाद के चलते नीलू दो साल से फ्रेंड्स कालोनी ग्वालियर रोड पर बने फ्लैट में अकेली रह रही थी। सुबह फ्लैट में कोई हलचल न होने पर मकान मालिक को संदेह हुआ। फ्लैट का दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो नीलू का शव पंखे से झूल रहा था। वहीं, मृतका की मां ने दामाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्वालियर रोड स्थित फ्रेंड्स कालोनी बालाजी टॉवर के बेसमेंट में बने फ्लैट में नीलू रायकवार (38) अकेली रह रही थी। सुबह फ्लैट का दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर कोई हलचल न होने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो नीलू का शव पंखे से झूल रहा था। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। नीलू के परिजनों ने बताया कि उसने करीब 13 साल पहले शिव प्रसाद निषाद से प्रेम विवाह किया था। शिव प्रसाद के दो बच्चे हैं। शादी के कुछ समय बाद से दोनों के बीच कलह बढ़ने लगी। इस कारण नीलू अलग रह रही थी। दीपावली पर वह बच्चों से मिलने फ्लैट कॉलोनी सिमरधा गई थी। इसके बाद लौटकर फ्लैट पर चली गई। सुबह सूचना मिली कि नीलू ने फंदा लगाकर जान दे दी। कोतवाली थाना प्रभारी राजेश पाल ने बताया कि छानबीन की जा रही है। परिजनों ने नीलू के आत्महत्या के कारणों के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। पिछले दिनों सर्किट हाउस पहुंचे कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के समक्ष भी पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। नीलू ने खुद को निषाद पार्टी महिला मोर्चा की पदाधिकारी होने का दावा करते हुए निषाद पार्टी के अध्यक्ष पर बैठक की सूचना न देने का आरोप लगाते हुए मंत्री संजय निषाद से शिकायत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सास ने कहा कि कई महिलाओं से अफेयर था। मृतक नीलू की मां ने बताया कि दामाद के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे, जब बेटी विरोध करती थी तो दामाद नीलू के साथ मारपीट करते थे। इसी वजह से महिला ने यह कदम उठाया है। दामाद अच्छा नहीं था। वो लड़ता था। दामाद की वजह से उसने जान दी है। हमारी लड़की कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। मां ने कहा कि मेरी बेटी बहुत दिलेर थी। रोते हुए मां ने बेटी के लिए इंसाफ की मांग की है। लड़कियों के साथ फोटो भी थी। दूसरी लड़कियों के साथ फोटो नीलू को भेजता था और प्रताड़ित करता था। नीलू के भाई ने कहा कि करीब सालभर पहले बहन और जीजा के बीच विवाद हो गया था। बहन किराये के फ्लैट में रही थी। हालांकि अब आना-जाना हो गया था। पुलिस जांच कर रही है। बहन के

प्रतापगढ़ में बड़ी घटना, मानिकपुर थाने के अंदर युवक ने धारदार हथियार से रेता अपना गला, थानाध्यक्ष निलंबित

मानिकपुर । चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए मानिकपुर थाने लाए गए युवक ने गुरुवार भोर थाने के अंदर ही धारदार हथियार से अपना गला रेत लिया। इससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। थानाध्यक्ष दीप नारायण को निलंबित कर दिया गया है। घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए एम्स रायबरेली भेजा गया है। वहां उसका उपचार चल रहा है। कुंडा कोतवाली के जमेठी गांव निवासी नरेंद्र सिंह का 22 वर्षीय बेटा शिवम सिंह 17 अक्टूबर से लापता था। स्वजन उसकी तलाश में जुटे थे। इसी बीच शिवम के मानिकपुर थाने में पांच दिनों से पूछताछ के लिए बैठाए जाने की जानकारी सामने आई। गुरुवार को सुबह करीब 11 बजे परिवार को यह जानकारी मिली कि शिवम ने थाने के अंदर ही किसी धारदार हथियार से अपना गला रेत लिया है। घबराए हुए स्वजन जब थाने पहुंचे तो उन्हें इस बात की जानकारी दी गई कि युवक रायबरेली भेजा गया है। मानिकपुर थाने में अपना गला रेतने वाले युवक शिवम सिंह की मां सावित्री देवी पिछले 5 दिनों से अपने बेटे की तलाश कर रही है। कहीं से जब उसे मानिकपुर थाने में उसके बेटे के होने की सूचना मिली तो वह गुरुवार की सुबह मानिकपुर थाने पहुंची। पुलिस कर्मियों से अपने बेटे की जानकारी लेनी चाही परंतु किसी ने कुछ बताने से इनकार कर दिया। बाहर खड़े लोगों से भी वह पूछती रही की क्या मेरे बेटे शिवम का पुलिस ने चालान कर दिया है। परंतु किसी ने कुछ नहीं बताया इतना ही नहीं अभी तक उसे किसी भी प्रकार की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

और वह निराश होकर अपने घर की ओर वापस लौट गई। इधर घटना की जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने मानिकपुर के थानाध्यक्ष मानिकपुर दीप नारायण को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए। एसपी ने बताया कि थाने में युवक तक धारदार हथियार कैसे पहुंचा, युवक को 5 दिन तक थाने में क्यों रखा गया, इस तरह के कई बिंदुओं की जांच का जिम्मा सीओ कुंडा अमरनाथ गुप्ता को दिया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह अगले सप्ताह मलेशिया में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। मोदी ने बृहस्पतिवार को फोन पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को यह सूचना दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह अगले सप्ताह मलेशिया में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। मोदी ने बृहस्पतिवार को फोन पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को यह सूचना दी। प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''मेरे प्रिय मित्र, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। उन्हें मलेशिया को आसियान की अध्यक्षता के लिए बधाई दी और आगामी शिखर सम्मेलनों की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।''उन्होंने कहा, ''आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होने और

आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्सुक हूं।'' दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) की बैठकें 26 से 28 अक्टूबर को होनी है। मलेशिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ-साथ आसियान समूह के वार्ता साझेदार कई देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। ट्रंप 26 अक्टूबर को दो दिवसीय यात्रा पर कुआलालंपुर जाएंगे। आसियान-भारत वार्ता संबंध 1992 में क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ शुरू हुए। यह दिसंबर 1995 में पूर्ण वार्ता साझेदारी और 2002 में शिखर सम्मेलन स्तरीय साझेदारी में परिवर्तित हो गया। दोनों देशों के बीच संबंध 2012 में रणनीतिक साझेदारी स्तर तक बढ़ गए। आसियान के 10 सदस्य देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमा और कंबोडिया शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें व्यापार और निवेश के साथ-साथ सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

दिवाली के बाद यूपी के तीन जिलों की हवा में घुला अधिक जहर

नोएडा । उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दीपावली पर दो दिन तक हुई आतिशबाजी ने हवा में जहर घोल दिया है। इसकी वजह से प्रदूषण इतना बढ़ा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) दो दिन में ही काफी बढ़ गया है। इससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायत भी है। कई शहरों में वायु गुणवत्ता गुरुवार को खराब और बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। जबकि पड़ोसी राज्य दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब स्थिति दर्ज की गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की साइट पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार, यूपी के मेरठ जिले में सुबह 10 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 332 दर्ज किया गया। जबकि हापुड़ जिले का 244 और बुलंदशहर का 214 दर्ज किया है। अधिक प्रदूषण वाले जिले एनसीआर में आते हैं। सिर्फ राजधानी लखनऊ की हवा खराब है।

यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 दर्ज किया गया है। एक्यूआई रेटिंग को अच्छा (0-50), संतोषजनक (51-100), मध्यम प्रदूषित (101-200), खराब (201-300), बहुत खराब (301-400), और गंभीर (401-500) श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस स्तर का प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सांस संबंधी दिक्कतों, आंखों में जलन, सिरदर्द और हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकता है। उन्होंने बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं, ये भी कहा है कि बाहर निकलने पर मास्क पहनने की सलाह भी दी है।

दिल्ली से पटना जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट वापस लौटी

नई दिल्ली दिल्ली से पटना जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट को गुरुवार को टेक ऑफ करने के तुरंत बाद दिल्ली वापस लौटना पड़ा। एयरलाइन कंपनी के अनुसार, क्रू को कुछ तकनीकी खराबी का शक हुआ, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। एयरलाइन कंपनी ने बताया कि बोइंग 737-8 एयरक्राफ्ट को डिटेल्ड इंस्पेक्शन के लिए ग्राउंडेड कर दिया गया है। दिल्ली के इंदिरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान की जांच चल रही है। एयरलाइन ने यात्रियों को हुई असुविधा को देखते हुए कंपनी दूसरी फ्लाइट से पटना भेजने का इंतजाम किया जा रहा है।

महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को घोषित किया सीएम फेस

मुकेश सहनी को महागठबंधन ने उपमुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया

पटना । बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस शुरू हो चुकी है। पटना के एक बड़े होटल में कांग्रेस, राजद, वामदल, वीआईपी और आईआईपी के प्रमुख नेता जुटे हैं। महागठबंधन ने स्पष्ट कहा कि पूरा गठबंधन एकजुट है। बिहार में बदलाव लाने के लिए तैयार है। भारी बहुमत से हमलोग सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि हमलोग पिछले साढ़े तीन साल से इस समय का इंतजार कर रहे थे। हमलोगों ने प्रण लिया था कि जब तक भाजपा को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज वह समय आ चुका है। चुनाव के बाद बिहार की जनता भाजपा को खदेड़ देगी। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं भाकपा माले के वरिष्ठ नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कुछ चंद सीटों के कारण हमलोग सरकार नहीं बना पाए। आज फिर से वह समय आया है। नीतीश सरकार ने छात्रों के साथ अन्याय किया। उनपर लाठियां बरसाई। महिलाओं को रोजगार योजना के नाम पर 10 हजार देकर छल किया। पूरे देश में लोगों को आशंका है कि क्या बिहार में महाराष्ट्र चुनाव वाला किस्सा दोहराया जाएगा। लेकिन, हम लोगों को आश्वस्त करते है कि बिहार बिल्कुल तैयार है। महागठबंधन के सातों दल पूरी एकता के साथ बदलाव के एजेंडे को पूरा करेंगे। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में एनडीए को अच्छी टक्कर दी। पिछले चुनाव में महागठबंधन मामूली वोटों के अंतर से पीछे रह गए। एनडीए संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग कर खेला करना चाहता है। यह लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के रूप में हमलोग तेजस्वी यादव को चुनते हैं। वह नौजवान हैं। जो कहते हैं करते हैं। अब तक जो वादे किए, उसमें खड़े उतरे। इसलिए महागठबंधन ने फैसला लिया है कि हमलोगों का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि मुकेश सहनी की पार्टी महागठबंधन के प्रमुख दलों में से एक है। उनकी छवि को देखते हुए महागठबंधन उन्हें डिप्टी सीएम का फेस घोषित करता है। इधर, प्रेस वार्ता शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता होटल पहुंचे। तेजस्वी यादव सबसे पहले अशोक गहलोत के कमरे में गए।

बंद कमरे में बातचीत हुई। इसके बाद दोनों नेता महागठबंधन के घटक दलों के प्रमुख नेताओं के साथ प्रेस वार्ता में पहुंचे। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले एक तस्वीर को लेकर विवाद हो गया। इसमें केवल नेता प्रतिपक्ष की ही तस्वीर है। इस पोस्टर के बाद सियासत गरमा गई।बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्थल पर लगे पोस्टरों से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तस्वीर गायब होने की बात कही। इसके बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने पलटवार कर कहा कि राहुल गांधी ही राजद और अन्य दलों के लिए बिहार में चुनाव प्रचार की मुख्य जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। हमें इन पोस्टरों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। प्रदीप भंडारी को सही समय आने पर इसका जवाब मिल जाएगा। वहीं इस मामले पर अमर उजाला ने भाकपा माले के वरिष्ठ नेता दीपांकर भट्टाचार्य से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो एक ही होता है। वहीं बुधवार को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने राजद प्रमुख लालू और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। बैठक के दौरान सीटों का विवाद, चुनाव प्रचार समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। राबड़ी आवास से निकलने के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ अच्छी बातचीत हुई। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। बिहार में कुल 243 सीटें है, और 5-10 सीटों पर आपसी सहमति से फ्रेंडली फाइट हो सकती है। हम मिलकर प्रचार करेंगे और चुनाव जीतेंगे।